भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2391

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

हाशिए पर पड़े जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना

2391. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं कि विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संस्थाओं/उद्यमियों के साथ साझेदारी का लाभ सबसे अधिक हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदायों तक पहुंचे;

(ख) क्या आदिवासी कारीगरों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद करने के लिए कोई वित्तीय या संभार तंत्र सहायता प्रदान की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश में आदिवासी समुदायों के बीच आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए अन्य ग्रामीण विकास संस्थानों के साथ ऐसे सहयोग का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) ट्राइफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर में आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन" (पीएमजेवीएम) योजना को क्रियान्वित कर रहा है। जनजातीय उत्पादों/उपजों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता की योजना के तहत, आदिवासी कारीगरों को सूचीबद्ध करना और उनसे विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद करना आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करने की मुख्य पहल है। उपरोक्त मुख्य पहल को प्राप्त करने के भाग के रूप में, ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ई-कॉमर्स और प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का खुदरा विपणन करता है। विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी से उत्पादन समूहों में उनके समावेश को प्राथमिकता देकर, प्रत्यक्ष रूप से बाजार तक पहुंच प्रदान करके और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र को क्रियान्वित करके जनजातीय उत्पादों की पहुंच का विस्तार किया जा सकता है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के तहत, ट्राइफेड ने हाशिए पर पड़े पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में 506 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए 506 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को स्वीकृति दी है।

ट्राइफेड ने आदिवासी कारीगरों/उत्पादकों द्वारा बनाए गए 13,000 से अधिक उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की सुविधा प्रदान की है।

*****